21 पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन

(Environment related Organizations & Conferences)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम *(UNEP)*

यूनेप का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन (स्टॉकहोम) में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस (1972) के परिणामस्वरूप हुआ। इसका मुख्यालय **नैरोबी (केन्या)** में है। संयुक्त राष्ट्र की यह एजेंसी पर्यावरणीय निरीक्षण और परिरक्षण के लिये अंतर-सरकारी (Inter-governmental) तरीकों के द्वारा समन्वय के लिये उत्तरदायी है। विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठनों के प्रबंधन के लिये अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया है। उदाहरण के लिये-1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल **(IPCC) का गठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और UNEP ने मिलकर ही किया था।** इसी तरह वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा (GEF) की क्रियान्वयन एजेन्सियों में यूनेप भी एक है।

यह एक ऐच्छिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय फंड भी है, जो विभिन्न पर्यावरणीय परियोजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। पर्यावरण से संबंधित प्रयासों के लिये इस संस्था द्वारा **ग्लोबल-500** पुरस्कार (वर्ष 1987 में स्थापित) भी दिया जाता है। हर साल 5 **जून** को मनाया जानेवाला विश्व पर्यावरण दिवस यूनेप (UNEP) की ही पहल है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972 में ही ले लिया गया था। हालाँकि, पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया। तब से हर साल यह मनाया जाता है।

आईयूसीएन *(International Union for Conservation of Nature-IUCN)*

आईयूसीएन विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है, जिसकी स्थापना **अक्तूबर 1948** में हुई। यह **'वर्ल्ड कन्जर्वेशन यूनियन'** के नाम से भी जाना जाता था। इसका मुख्यालय **ग्लाण्ड (Gland), स्विट्ज़रलैंड** में है, जो जेनेवा के निकट है। आईयूसीएन में सरकारी संगठन और गैर-सरकारी संगठन दोनों सदस्य होते हैं। 200 से ज़्यादा सरकारी संगठन और 1000 से ज़्यादा गैर-सरकारी संगठन IUCN के सदस्य हैं।

आईयूसीएन का मिशन एवं दृष्टिकोण

- आईयूसीएन पर्यावरण एवं विकास से जुड़ी अधिकांश चुनौतियों के लिये व्यावहारिक समाधान विकसित करने का प्रयास करता है। यह वैज्ञानिक शोध का समर्थन करता है, पूरे विश्व में फील्ड प्रोजेक्टों का प्रबंधन करता है तथा सरकारी, गैर-सरकारी, संयुक्त राष्ट्र, विभिन्न कंपनियों एवं स्थानीय समुदायों को एकजुट करता है ताकि नीतियों एवं कानूनों का क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो सके।
- पूरे विश्व में फैले विभिन्न समाजों को प्रभावित करना तथा उनकी मदद करना जिससे वे जैव विविधता का संरक्षण कर यह सुनिश्चित कर सकें कि किसी भी प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल पूर्णतः न्यायसंगत और संपोषणीय हो ताकि **पर्यावरण संरक्षण** और **गरीबी निवारण** साथ-साथ हो सकें।
- जैव विविधता का संरक्षण अर्थात् पौधों एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकना एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही आईयूसीएन का मुख्य कार्य है। इसलिये यह संकटग्रस्त जीव-जन्तुओं की एक सूची जारी करता है, जिसे **'रेड डाटा बुक'** कहते हैं।

आईयूसीएन जैव विविधता संरक्षण के अलावा चार अन्य क्षेत्रों पर भी कार्य करता है-

- जलवायु परिवर्तन (Climate Change)
- संपोषणीय ऊर्जा (Sustainable Energy)
- आजीविका (Livelihood)
- हरित अर्थव्यवस्था (Green Economy)

आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र महासभा का 'पर्यवेक्षक दर्जा' (Observer Status) प्राप्त एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित मुद्दों को देखता है। इस तरह **आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं** है।

वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड *(World Wildlife Fund-WWF)*

वर्ल्ड वाइड फण्ड फॉर नेचर एक **अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन** है, जो 1961 में स्विट्ज़रलैण्ड के मोर्जेस में एक **धर्मार्थ ट्रस्ट (Charitable Trust)** के रूप में गठित हुआ था। यह **विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण**

विश्व बैंक समूह की पर्यावरण रणनीति *2012-22*
(World Bank Group Environment Strategy – 2012-22)

विश्व बैंक समूह की पर्यावरण रणनीति 2012-22 (Environment Strategy 2012-22) एक महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना है जो विकासशील देशों में गरीबी निवारण और विकास को बढ़ावा देकर एक 'हरे-भरे, स्वच्छ और प्रतिरोधक (Green, Clean and Resilient) पर्यावरण का निर्माण करना चाहती है। इस प्रकार इसका उद्देश्य वृद्धि के साथ-साथ संपूर्ण और संपोषणीय विकास को बढ़ावा देना है।

इस पर्यावरण रणनीति में विश्व बैंक के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) और MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) जैसी बड़ी संस्थाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान है। व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित विश्व के 2300 बैंक समूहों के हितधारकों के साथ यह योजना विश्व में **'सभी के लिये स्वच्छ, हरे और प्रतिरोधक क्षमता वाले पर्यावरण' (Clean, Green, Resilient World for All)** की परिकल्पना पर कार्य कर रही है। इनका मानना है कि विकासशील देशों को गरीबी निवारण और जीवन का एक उचित स्तर प्राप्त करने के लिये तीव्र विकास की आवश्यकता है लेकिन जब तक इनका विकास होगा पर्यावरणीय संकट भी अपने चरम पर पहुँच जाएगा। इसलिये ऐसी कार्यनीति को अपनाना आवश्यक है जो पर्यावरण और विकास में बेहतर समन्वय स्थापित कर सके।

यह कार्ययोजना मुख्यत: तीन बातों पर संकेन्द्रित है- हरा, स्वच्छ और प्रतिरोधक क्षमता।

हरा *(Green)*

हरे का आशय एक ऐसे विश्व से है जो प्राकृतिक संसाधनों, जिसमें सागर, भूमि व वन भी शामिल हैं, का संपोषणीय रूप से संरक्षण व प्रबंधन करते हुए आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इसमें जैव विविधता को बनाए रखते हुए मृदा संरक्षण और समुद्री पारितंत्र को स्वस्थ रखना भी शामिल है।

स्वच्छ *(Clean)*

स्वच्छ का आशय विश्व के सभी लोगों के लिये बेहतर स्वास्थ्य एवं उत्पादक जीवन सुनिश्चित करने, प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल एवं स्वच्छ सागरीय पारितंत्र प्रदान करने से है। इसका उद्देश्य एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है, जहाँ विकास की रणनीतियाँ ऐसी हों कि प्रदूषण मुक्त वातावरण, जलवायु अनुकूल कृषि, स्वच्छ ऊर्जा और सतत् शहरी विकास के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके।

प्रतिरोधक क्षमता *(Resilient)*

प्रतिरोधक क्षमता का आशय जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली हानि व संकटों (Shocks) से निपटने के लिये पूर्णरूप से तैयार होने और सक्षम बनने से है। स्वस्थ और बेहतर रूप से प्रबंधित पारितंत्र अधिक लोचदार होते हैं अर्थात् जलवायु परिवर्तन प्रभावों से निपटने और सुभेद्यता (Vulnerability) को कम करने में सक्षम होते हैं, जिससे आपदा के कारण हानि कम से कम होती है। विश्व बैंक समूह विभिन्न देशों को उनके बेहतर तट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूल कृषि के लिये वित्तीय सहायता और जोखिम बीमा (Risk Insurance) प्रदान करता है।

इस तरह विश्व बैंक की पर्यावरणीय रणनीति राष्ट्रों को अपने विकास के साथ-साथ भविष्य के पर्यावरणीय संकटों के प्रति भी सुदृढ़ बनाती है ताकि एक बेहतर विश्व का निर्माण हो सके।

वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी
(Wildlife Conservation Society-WCS)

वैश्विक स्तर पर वन्यजीवों और वन्य स्थानों को संरक्षित करने के लिये समर्पित एक संस्था वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी (WCS) है। इस कार्य को पूरा करने के लिये यह **'विज्ञान, संरक्षण कार्य और शिक्षा (Science, Protection Work and Education)** को बढ़ावा देती है। इससे लोगों की प्रकृति के प्रति मनोवृत्ति और व्यवहार में बदलाव आता है और वे इस महत्त्व को समझने लगते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिये वन्यजीवों और मनुष्यों के बीच सामंजस्य का होना अनिवार्य है।

वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी का लक्ष्य मुख्य रूप से उन 15 क्षेत्रों को प्राथमिकता देना है, जो विश्व की 50% से अधिक जैव विविधता धारण करते हैं। इसके लिये WCS ने एक '2020 रणनीति' बनाई है। WCS 'विज्ञान' का उपयोग कर इस प्राकृतिक विश्व को समझने का प्रयास करता है। उसके इस ज्ञान का उपयोग नीति-निर्माता, समुदाय और लाखों लोग वन्यजीव संरक्षण के लिये उचित कदम उठाने में करते हैं।

WCS-India कार्यक्रम

सभी भारतीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए भारत के वन्यजीवों और स्थलों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी इंडिया कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी और गैर-सरकारी सहयोगियों के सम्मिलित प्रयासों से बाघों व अन्य वन्यजीवों पर शोध, क्षमता निर्माण और प्रभावी स्थान-आधारित (Site-Based) संरक्षण प्रदान करना है। इसके अलावा यह स्थानीय समुदायों के सहयोग से मानव-पशु संघर्ष को कम करने का प्रयास भी करता है।

स्थानीय ग्रामीण आकलन *(Local Rural Assessment)*

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत पूरे भारत में ग्राम परिषदों के लिये 'पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) को अनिवार्य कर दिया गया है। भारत, स्थानीय आकलन PBR की तैयारी के लिये एक तरीका प्रदान करता है।

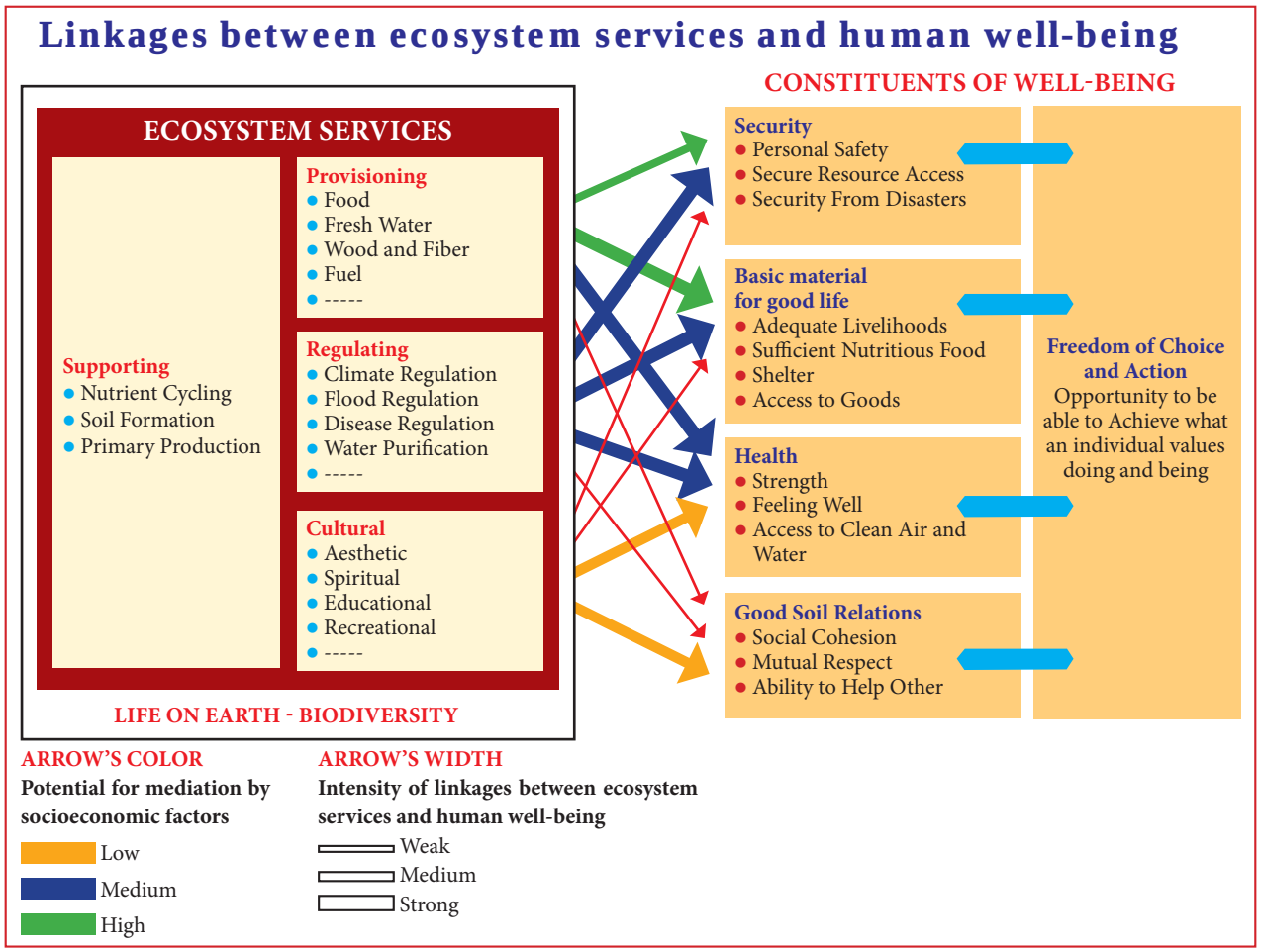

स्मरणीय तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण मामलों पर मुख्य एजेंसी है। इसका गठन महासभा की 1972 की स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस में हुआ। इसके स्थापना दिवस (5 जून) को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- IUCN विश्व का सबसे पुराना एवं बड़ा वैश्विक पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण का नेटवर्क है। इसका मुख्यालय ग्लाण्ड (स्विट्ज़रलैंड) में है। इसके द्वारा 'रेड डाटा बुक' का प्रकाशन किया जाता है।
- साइट्स (CITES) लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु उनके व्यापार के विनियमन का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत इसमें 1976 में शामिल हुआ।
- प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन (CMS) इनके प्रवास रेंज वाले देशों में संरक्षण हेतु सरकारों के मध्य एक संधि है। इसे 1979 में UNEP की पहल पर हस्ताक्षरित किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (IWMI) एक **गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन** है, जो विकासशील देशों में जल और भूमि संसाधनों के सतत् उपयोग को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय कोलम्बो (श्रीलंका) में है।
- UNFF का मुख्य उद्देश्य वनों का संरक्षण प्रबंधन एवं सतत् विकास को बढ़ावा देना है।
- ट्रैफिक एक अग्रणी गैर-सरकारी वैश्विक नेटवर्क है, जो वन्यजीवों और पौधों के व्यापार पर निगरानी रखता है और उसके उचित प्रबंधन पर बल देता है